यू. पी. राज्य

बनाम

चरण सिंह

(2007 की सिविल अपील सं 2381)

26 मार्च, 2015

[न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर. भानुमती]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947–उपधारा 6एन और 4के–छंटनी–अस्थाई कर्मचारी होने के कारण ट्यूबवेल ऑपरेटर की सेवाओं की समाप्ति–नोटिस के बदले कर्मी को एक माह का वेतन दिया गया–को चुनौती– औद्योगिक न्यायाधिकरण ने बर्खास्तगी को अवैध ठहराया, कामगार की बहाली के लिए एक फैसला पारित किया लेकिन कोई बकाया वेतन नहीं दिया– इसके अनुपालन में, कामगार को मछुआरे के पद पर नियुक्ति पत्र की पेशकश की– हालाँकि, बार-बार ताकीद करने के बावजूद कामगार ने ग्रहण करने से इनकार कर दिया– इसके बाद, उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार उसे देय राशि का संपूर्ण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी, बहाली के लिए फैसला पारित होने की तिथि अर्थात 24.2.1997 से 31.1.2005 तक ही–अपील पर, अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि राज्य उस अवधि के लिए कामगार को देय पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि राज्य ने प्रतिवादी को समकक्ष पद पर बहाल करने के फैसले के बावजूद मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से कई वर्षों तक कामगार को नौकरी से बाहर रखा है– इस प्रकार, मछुआरे की ड्यूटी के लिए रिपोर्ट न करना, जो समकक्ष पद नहीं था, कामगार की ओर से अनुचित नहीं कहा जा सकता– कामगार ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिन काम किया– जो कार्य कामगार द्वारा किया गया वह अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में अभी भी विद्यमान है– अपीलकर्ता द्वारा उपधारा 6-एन और 6-डब्ल्यू के प्रावधानों के तहत शर्तों न्यायालयों ने बहाली का सही फैसला सुनाया– हालाँकि, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने बकाया वेतन न देकर गलती की और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी बर्खास्तगी की तारीख से पुरस्कार पारित होने की तारीख तक पिछला वेतन न देना उचित नहीं था, भले ही वह लाभप्रद रूप से नियोजित था– इसके अलावा, कामगार चार दशकों से इस मामले पर लड़ रहा है– इस प्रकार, आदेश एक्सएलआई नियम 33 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, कामगार को

संबंधित अवधि के लिए पिछला वेतन दिया जाएगा, भले ही कामगार ने इस पर सवाल उठाते हुए अलग से रिट याचिका दायर नहीं की– राज्य को कामगार के पक्ष में बर्खास्तगी आदेश की तारीख से फैसले की तारीख तक 50% बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया– 24.02.1997 से 31.01.2005 की अवधि के लिए पूर्ण बकाया वेतन देने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित:

1.1 उच्च न्यायालय ने सही माना कि राज्य 24.2.1997 से 31.1.2005 की अवधि के लिए श्रमिक को देय पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित प्रतिवादी को समकक्ष पद पर बहाल करने के फैसले के बावजूद राज्य ने मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से कई वर्षों तक कामगार को नौकरी से बाहर रखा है। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा उसे दिये गए मछुआरे के काम के लिए इस आधार पर रिपोर्ट न करना कि उक्त पद ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर नहीं है, प्रतिवादी की ओर से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। प्रस्तावित पद पर रिपोर्ट न करने के लिए प्रतिवादी पर दोष मढ़ना, नियोक्ता की ओर से एक बार फिर अनुचित है। इस प्रकार, "काम नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धांत का तत्काल मामले की तथ्यात्मक स्थिति में कोई महत्व नहीं है। [पैरा 12, 20 और 21] 816-बी-सी; 825-सी-डी]

1.2 उक्त विभाग के कामगार की सेवाओं की समाप्ति का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा कानूनी रूप से तय किया जा सकता है क्योंकि यह मामला प्रविष्टि संख्या 10 में दूसरी अनुसूची के साथ पढ़े गए अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है। इस प्रकार, नीचे के न्यायालयों ने सही माना कि अपीलकर्ता द्वारा कामगार की सेवाओं की समाप्ति के संबंध में उठाया गया विवाद एक औद्योगिक विवाद है। [पैरा 12] [816-ई-जी]

1.3 प्रतिवादी-कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिन काम किया है और औद्योगिक न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर दलीलों और सबूतों के आधार पर तथ्य की खोज को सही ढंग से दर्ज किया कि जो काम प्रतिवादी-कामगार द्वारा किया जा रहा था अपीलकर्ता के संस्थापन में अभी भी अस्तित्व में है। औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष यह कहा गया था कि ट्यूब-वेल ऑपरेटर का काम अब "मछुवा" जैसे अन्य कामगारों द्वारा ले लिया गया है और कुछ ट्यूब-वेल ऑपरेटरों को अन्य पदों पर भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, दिए गए बयानों के मद्देनजर, यह पूरी तरह से

स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 6-एन और 6-डब्ल्यू के प्रावधानों के तहत आवश्यक शर्तों का अपीलकर्ता द्वारा पालन नहीं किया गया था और अपीलकर्ता-विभाग का प्रस्तुतीकरण यह है कि संबंधित कामगार को अस्थायी कर्मचारी मानकर उसके एक महीने का वेतन भुगतान किया गया था, जो कानून में संघारणीय नहीं है और इसने प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को अवैध बना दिया है और इसलिए; नीचे के दोनों न्यायालयों ने इसे सही ढंग से रद्द कर दिया है और क्रमशः बहाली और 'बकाया वेतन' का पुरस्कार पारित किया है। हालाँकि, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी को पिछला वेतन नहीं देना और उच्च न्यायालय द्वारा केवल 24.2.1997 से 31.1.2005 के बीच की अवधि के लिए भुगतान करना, बिना किसी ठोस कारण बताए किया गया है, भले ही वह लाभप्रद रूप से नियोजित हो और अपनी सेवाओं से समाप्ति की तारीख, यानी 22.08.1975 से इसके लिए कानूनी रूप से हकदार है, जिसे कानून में वैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, उसकी समाप्ति की तारीख, यानी 22.08.1975 से पिछले वेतन के भुगतान से इनकार करना कानून में पूरी तरह से अक्षम्य है और पिछला वेतन देकर इसे संशोधित करने की आवश्यकता है। [पैरा 13] [816-जी-एच; 817-ए-एच]

1.4 औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा बिना कोई ठोस और वैध कारण बताए उक्त अवधि के लिए बकाया वेतन देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, प्रतिवादी को पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया गया, भले ही औद्योगिक न्यायाधिकरण ने विवादास्पद प्रश्न संख्या 1 पर अपना निष्कर्ष उसके पक्ष में सकारात्मक दर्ज किया हो और संबंधित अवधि के दौरान प्रतिवादी के लाभकारी रोजगार के साक्ष्य के अभाव में, प्रतिवादी की गलती के बिना औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग है और यह कानून के विपरीत है। इसलिए, यह इस न्यायालय के लिए एक उपयुक्त मामला है कि वह प्रतिवादी को बकाया वेतन देने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश एक्सएलआई नियम 33 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे, भले ही प्रतिवादी ने फ़ैसले के उस हिस्से पर सवाल उठाते हुए एक अलग रिट याचिका दायर नहीं की है, जिसमें प्रासंगिक अवधि के लिए नीचे के न्यायालयों द्वारा उसे कोई पिछला वेतन नहीं दिया गया था। [पैरा 17] [819-डी-एच]

1.5 औद्योगिक न्यायाधिकरण की ओर से प्रतिवादी को पिछला वेतन देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं था, भले ही यह पाया गया हो कि अधिनियम की धारा 6-एन के तहत अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण समाप्ति का

आदेश कानून की दृष्टि से शुरू से ही अमान्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाप्ति की अवधि वर्ष 1975 में थी और नियोक्ता द्वारा 40 वर्षों से अधिक समय से औद्योगिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष मामले को अनावश्यक रूप से चुनौती दी गई है। प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्य चार दशकों से अधिक समय से पीड़ित हैं क्योंकि उनकी आजीविका के स्रोत को अपीलकर्ता ने मनमाने ढंग से वंचित कर दिया है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार से अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को वंचित कर दिया गया है। [पैरा 20 और 22) [824-जी-एच; 825-ए-बी, ई-एफ] [827-ई-जी]

ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम और अन्य 1985 (2) पूरक एससीआर 51: (1985) 3 एससीसी 545–संदर्भित किया गया।

1.6 अपीलकर्ता समाप्ति आदेश की तारीख से औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित फ़ैसले की तारीख तक प्रतिवादी के पक्ष में 50% बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। प्रतिवादी को 24.02.1997 से 31.01.2005 की अवधि के लिए पूर्ण बकाया वेतन देने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है। [पैरा 23 और 24)

यूपी राज्य और अन्य बनाम अरुण कुमार सिंह (1995) पूरक (4) एससीसी 241; *बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन कर्मचारी संघ, प्रभादेवी टेलीफोन एक्सचेंज बनाम भारत संघ एवं अन्य* 1997 (2) पूरक एससीआर 1: (1997) 6 एससीसी 723; *दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बनाम बसंती देवी और अन्य* 1999 (3) सप्ल एससीआर 219: (1999) 8 एससीसी 229; *दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय* 2013 (9) एससीआर 1: (2013) 10 एससीसी 324; *भुवनेश कुमार द्विवेदी बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड* (2014) 11 एससीसी 85–संदर्भित किए गए।

निर्णय विधि संदर्भ

(1995) पूरक (4) एससीसी 241	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1997 (2) पूरक एससीआर 1	संदर्भित किया गया	पैरा 9
1999 (3) पूरक एससीआर 219	संदर्भित किया गया	पैरा 17
2013 (9) एससीआर 1	संदर्भित किया गया	पैरा 18

(2014) 11 एससीसी 85	संदर्भित किया गया	पैरा 19
1985 (2) पूरक एससीआर 51	संदर्भित किया गया	पैरा 22

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: 2007 से सिविल अपील संख्या 2381

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 1998 की रिट याचिका सं 2588 में दिनांक 18.07.2006 के निर्णय और आदेश से।

गौरव भाटिया, एएजी, गौरव श्रीवास्तव, प्रगति नीखरा अपीलार्थी के लिए।

जी. वी. राव, ए. के. उपाध्याय, देवेंद्र सिंह उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था-

न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा

1. यह अपील 1998 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 2588 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 18.07.2006 के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने 1992 के न्यायनिर्णयन मामले संख्या 139 में औद्योगिक न्यायाधिकरण दिनांक 24.02.1997 द्वारा पारित फ़ैसले को बरकरार रखा और संशोधित किया है।

2. पक्षों की ओर से आग्रह किए गए तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों को यहां संक्षेप में बताया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश इस न्यायालय द्वारा अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार के अभ्यास में हस्तक्षेप की गारंटी देता है या नहीं।

3. प्रतिवादी को मत्स्य पालन विभाग, मेरठ (यूपी) के सहायक निदेशक द्वारा 06.03.1974 से अस्थायी ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाएँ दिनांक 22.08.1975 के पत्र द्वारा यह कहते हुए समाप्त कर दी गईं कि वह एक अस्थायी कर्मचारी था और विभाग को अब उसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। नोटिस के बदले उसे एक माह का वेतन दिया गया था। 01.05.1976 को, प्रतिवादी ने सुलह अधिकारी, मेरठ के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी का रोजगार अपीलकर्ता द्वारा गलत तरीके से समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वह मत्स्य पालन विभाग का एक स्थायी कर्मचारी है और और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 6-एन

के तहत प्रावधान, जो प्रकृति में अनिवार्य हैं, का अनुपालन नहीं किया गया है और इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति अवैध है। मामले को निर्णय के लिए सुलह अधिकारी से श्रम आयुक्त, कानपुर को स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रतिवादी ने इस न्यायालय सहित विभिन्न उच्च कार्यालयों और न्यायालयों के समक्ष कई अभ्यावेदन दिए, जिसमें इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए 09.09.1986 को सचिव, यूपी राज्य कानूनी सहायता और सलाहकार बोर्ड को भेज दिया गया, जिसने इसके बजाय प्रतिवादी को परामर्श के लिए सभापति, जिला न्यायाधीश, जिला कानून सहायता और सलाहकार, सिविल कोर्ट परिसर, मेरठ से संपर्क करने का निर्देश दिया।

4. इसके बाद, प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा 4-के के प्रावधानों के तहत औद्योगिक विवाद के संदर्भ के लिए राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन दायर किया और राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 14499-502 एमआरआईआर ओपी 395/91, दिनांक 24.10.1992 के माध्यम से विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण, मेरठ को भेज दिया, जिससे इसके निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए:

i. क्या कर्मचारी की सेवाएँ अवैध रूप से समाप्त कर दी गई हैं, और

ii. क्या अधिनियम की धारा 6-एन का कोई उल्लंघन है?

5. औद्योगिक न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी कानूनी दलीलों पर विचार करने के बाद, प्रतिवादी के पक्ष में उसे संदर्भित प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसमें कहा गया है कि श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति अवैध थी और रद्द किए जाने योग्य थी। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता को ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के समकक्ष किसी भी पद पर प्रतिवादी को बहाल करने का निर्देश दिया। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने 24.02.1997 से श्रमिक की बहाली के लिए एक फैसला पारित किया। हालाँकि, कामगार को कोई बकाया वेतन नहीं दिया गया। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित फैसले के अनुसरण में, अपीलकर्ता ने अपने आदेश दिनांक 03.05.1999 के तहत प्रतिवादी कामगार को 2610-60-3150- 65-3400/- के वेतनमान में मछुआरे के पद पर नियुक्ति पत्र की पेशकश की। हालाँकि, अपीलकर्ता के बार-बार अनुस्मारक के बाद भी प्रतिवादी कर्मचारी ने उक्त पद पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक विविध रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी कर्मचारी को "मछुवा" के पद पर बहाल

किया गया है, जो उनका दावा था कि ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर था। चूँकि प्रतिवादी कामगार ने अपीलकर्ता के कई पत्रों का जवाब नहीं दिया जो उसे काम पर वापस बुला रहा था, वह "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत पर 24.02.1997 से 31.01.2005 की अवधि के लिए किसी भी वेतन का हकदार नहीं है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और माना कि राज्य सरकार ने कामगार को कई वर्षों तक नौकरी से बाहर रखा था और इसलिए, राज्य सरकार उपर्युक्त अवधि के लिए कामगार को देय पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

7. उक्त आक्षेपित निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता द्वारा इसे रद्द करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान अपील दायर की गई है और इस न्यायालय से विभिन्न तथ्यों और कानूनी तर्कों का आग्रह करके ऐसे आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है जो यह न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।

8. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) श्री गौरव भाटिया द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका को गलत तरीके से निस्तारित कर दिया है कि उप निदेशक मत्स्य पालन, मेरठ के कार्यालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.1999 के अनुसार, प्रतिवादी को 2610-60-3150-65-3400/- के वेतनमान पर मछुआरा (मछुआ) के पद पर नियुक्ति दी गई, जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद के बराबर है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी द्वारा ट्यूब-वेल ऑपरेटर के रूप में रखा गया पद अस्थायी था और स्वीकृत पद नहीं था क्योंकि उन्हें विभाग में काम की उपलब्धता के अनुसार ही पद सौंपा गया था। उपरोक्त आदेश के अनुसार मछुआरे के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद भी, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा उसे भेजे गए कई पत्रों और अनुस्मारक के बावजूद, प्रतिवादी ने यह कहते हुए उपरोक्त पद का कार्यभार नहीं संभाला कि यह एक ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर नहीं है।

9. अपीलकर्ता के लिए विद्वान एएजी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मत्स्य पालन विभाग अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *यूपी राज्य और अन्य बनाम अरुण कुमार सिंह*[1] और *बॉम्बे टेलीफोन कैंटीन कर्मचारी एसोसिएशन, प्रभादेवी टेलीफोन एक्सचेंज बनाम भारत संघ और अन्य*[2] के मामलों में तय किया गया है।

10. विद्वान एएजी द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी ने मछुआरे के पद पर अपनी सेवाओं में योगदान नहीं दिया है और इसलिए, "काम नहीं तो वेतन नहीं" सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि इस न्यायालय ने कई मामलों में माना है, प्रतिवादी उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 24.02.1997 से 31.01.2005 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 6-एच के तहत किसी भी मौद्रिक लाभ का हकदार नहीं है। इस प्रकार, नीचे दी गई दोनों अदालतों के निष्कर्ष गलत हैं और कानून में त्रुटि से ग्रस्त हैं और इसलिए, इन्हें इस न्यायालय द्वारा कायम रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से विद्वान वकील श्री जी.वी.राव द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी की सेवाओं को समाप्त करना कानूनन गलत है क्योंकि उसकी सेवाएं अवैध रूप से इस आधार पर समाप्त कर दी गई हैं कि वह एक अस्थायी कर्मचारी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पूरी तरह से अधिनियम के दायरे में आती हैं और प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं को उसके पद से समाप्त करना छंटनी के समान है और चूंकि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया है, वह अधिनियम की धारा 6-एन के प्रावधान के तहत प्रदान किए गए लाभों का हकदार है। चूँकि, अपीलकर्ता ने अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी का दिनांक 22.8.1975 का समाप्ति आदेश रद्द किए जाने योग्य है और वह पिछले वेतन के साथ बहाली का हकदार है, क्योंकि मछुआरे का पद ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद के समकक्ष नहीं है।

12. हमने दोनों पक्षों को सुना है। पार्टियों की ओर से दिए गए उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी कानूनी तर्कों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि राज्य 24.2.1997 से 31.1.2005 की अवधि तक कामगार को देय पूरी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी को समकक्ष पद पर बहाल करने के फैसले के बावजूद राज्य ने मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से कई वर्षों तक कामगार को नौकरी से बाहर रखा है। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा उसे दी गई मछुआरे के काम के लिए प्रस्तुत न होना प्रतिवादी की ओर से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। हमारे द्वारा निकाले गए उपरोक्त निष्कर्षों के समर्थन में, हम अपने कारणों को इस प्रकार दर्ज करते हैं:-

औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा यह पहले ही सही माना जा चुका है कि मत्स्य पालन विभाग अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित "उद्योग" की परिभाषा के अंतर्गत आता है और औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से आरडब्ल्यू 1 और ईडब्ल्यू 1, श्री आर बी माथुर के बयान के अनुसार भी, क्योंकि कर्मचारियों को नियुक्त करने से अपीलार्थी-विभाग की स्थापना का उद्देश्य पूरा होता है तथा विभाग नियमित रूप से चलता है। इस प्रकार, उक्त विभाग के कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति का मामला औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा कानूनी रूप से तय किया जा सकता है क्योंकि यह मामला प्रविष्टि संख्या 10 में दूसरी अनुसूची के साथ पढ़े गए अधिनियम के प्रावधानों के तहत आता है। इस प्रकार, निचली अदालतों द्वारा यह सही माना गया है कि अपीलकर्ता द्वारा श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति के संबंध में उठाया गया विवाद एक औद्योगिक विवाद है।

13. इसके अलावा, यह एक सुस्थापित तथ्य है कि प्रतिवादी-कर्मचारी ने एक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिन काम किया है और औद्योगिक न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर दलीलों और सबूतों के आधार पर तथ्य की खोज को सही ढंग से दर्ज किया है कि जो काम प्रतिवादी-कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था वह अभी भी अपीलकर्ता की स्थापना में मौजूद है, औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष प्रतिवादी के साथ-साथ नियोक्ता के गवाह द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। इसके अलावा, श्री आर बी माथुर ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्यूब-वेल ऑपरेटर का काम अब "मछुवा" जैसे अन्य कामगारों द्वारा ले लिया गया है और कुछ ट्यूब-वेल ऑपरेटरों को अन्य पदों पर भी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, उनके द्वारा ऊपर दिए गए बयानों के मद्देनजर, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 6-एन और 6-डब्ल्यू के प्रावधानों के तहत आवश्यक शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था और अपीलकर्ता-विभाग का एकमात्र तर्क यह है कि संबंधित कर्मचारी को अस्थायी कर्मचारी मानते हुए एक महीने का वेतन दिया गया था। अपीलकर्ता की ओर से विद्वान एएजी का यह तर्क, हालांकि, कानून में संघारणीय नहीं है और इसने प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश को अवैध बना दिया है और इसलिए, नीचे की दोनों अदालतों ने इसे सही ढंग से रद्द कर दिया है और क्रमशः बहाली और बकाया वेतन का फैसला पारित किया है। हालाँकि, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादी को पिछला वेतन नहीं देना और उच्च न्यायालय द्वारा केवल 24.2.1997 से 31.1.2005 के बीच की अवधि के लिए भुगतान करना, बिना किसी ठोस कारण बताए किया गया है, भले ही वह लाभप्रद रूप से नियोजित हो और

अपनी सेवाओं से समाप्ति की तारीख, यानी 22.08.1975 से इसके लिए कानूनी रूप से हकदार है, जिसे कानून में वैध नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के समकक्ष पद पर उनकी बहाली और उनकी समाप्ति की तारीख, यानी 22.08.1975 से बकाया वेतन का भुगतान करने से इनकार करने के संबंध में नीचे की अदालतों द्वारा पारित निर्णय और आदेश पूरी तरह से अस्थिर है क्योंकि यह कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है और बकाया वेतन देकर इसे संशोधित करने की आवश्यकता है।

14. विद्वान एएजी ने आगे तर्क दिया कि कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति सरकारी आदेश दिनांक 30.07.1975 के मद्देनजर की गई थी, जिसके द्वारा ट्यूबवेल ऑपरेटर का पद समाप्त कर दिया गया था और प्रतिवादी-कामगार को समाप्ति पत्र दिया गया था क्योंकि वह एक अस्थायी कर्मचारी था। हालाँकि, इन कारणों को अपीलकर्ता द्वारा उनके समाप्ति पत्र दिनांक 22.08.1975 में नहीं बताया गया था और इसके बजाय, यह उल्लेख किया गया था कि उनकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है जो अधिनियम की धारा 2 (एस) के तहत परिभाषित प्रतिवादी की छंटनी के समान है। इस प्रकार, प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति के पत्र में बताए गए अपुष्ट कारण को देखते हुए, इस संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को हमारे द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, शासनादेश दिनांक 30.07.1975 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नलकूप मैकेनिक का पद सृजित किया जा रहा है जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का कार्य करेगा। इसलिए, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पद समाप्त नहीं किया गया, बल्कि केवल पद का नाम बदल दिया गया, जैसा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सही माना है।

15. इसलिए, उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा विवादास्पद बिंदु पर अपने फैसले में दिए गए कारणों के अवलोकन पर, अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उपर्युक्त सरकारी आदेश के अनुसार कामगार की सेवाओं की समाप्ति की गई थी को हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह कानून में गलत है। यह तथ्य कि उनसे कनिष्ठ व्यक्ति और उनके समकालीन अभी भी अपीलकर्ता-विभाग के लिए काम कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि प्रतिवादी की सेवाओं की समाप्ति अविवेकपूर्ण और अनुचित तरीके से की गई है।

16. अब, प्रतिवादी कामगार को बकाया मजदूरी के अधिकार के सवाल पर आते हुए, इसका उत्तर सकारात्मक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कामगार ने

मछुआरे के रूप में नई नौकरी, जो उसे औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा इस आधार पर पारित फ़ैसले के अनुसार कि उक्त पद ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर नहीं है के बाद में पेश की गई थी, स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। भले ही अपीलकर्ता औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार दिनांक 24.02.1997 की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हो गया था और उसे बहाली की पेशकश की थी, यह काम करने वाले के अधिकार में है कि वह उसे दी गई नई नौकरी से इनकार कर दे और इसे प्रतिवादी-कर्मचारी की ओर से अनुचित या ग़लत नहीं कहा जा सकता।

17. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-कर्मचारी की सेवाओं की समाप्ति को उचित ठहराने के लिए अपीलकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर पेश किए गए ठोस सबूतों का अभाव है, जो समाप्ति की तारीख से लेकर औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा फैसला पारित करने की तिथि तक बकाया वेतन न दिए जाने से व्यथित है। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा बिना कोई ठोस और वैध कारण बताए उक्त अवधि के लिए बकाया वेतन देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए, संबंधित अवधि के दौरान प्रतिवादी के लाभकारी रोजगार के साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी की गलती के बिना भी प्रतिवादी को बकाया वेतन देने से इनकार करना, हालांकि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने विवादास्पद प्रश्न संख्या 1 पर अपना निष्कर्ष उसके पक्ष में सकारात्मक दर्ज किया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग है और यह इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित कानून के विपरीत है। इसलिए, इस न्यायालय के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश एक्सएलआई नियम 33 के तहत प्रतिवादी को बकाया वेतन देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करना एक उपयुक्त मामला है, भले ही प्रतिवादी ने फ़ैसले के उस हिस्से जिसमें प्रासंगिक अवधि के लिए नीचे के न्यायालयों द्वारा उसे कोई पिछला वेतन नहीं दिया गया था पर सवाल उठाते हुए एक अलग रिट याचिका दायर नहीं की हो। प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उक्त प्रावधान पर भरोसा करने और इस न्यायालय को यह दिखाने का अधिकार है कि नीचे के दोनों न्यायालयों द्वारा आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार में प्रासंगिक अवधि के लिए बकाया वेतन देने से इनकार करने में दर्ज किए गए निष्कर्ष कानून की नजर में खराब हैं क्योंकि यह न केवल गलत है बल्कि कानून में त्रुटि भी है। इसलिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश एक्सएलआई नियम 33 के तहत इस न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई शक्ति के अनुसार और दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग बनाम बसंती देवी और अन्य[3] में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में, हम मानते हैं कि राज्य सरकार प्रतिवादी को उसके समाप्ति आदेश दिनांक 22.08.1975 से औद्योगिक न्यायाधिकरण

द्वारा पारित पुरस्कार की तिथि, यानी 24.02.1997 तक पिछले वेतन का 50% भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उपर्युक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

"17. अपने दृष्टिकोण में हम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 33 के प्रावधानों से भी शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो इस प्रकार है:

33. अपील न्यायालय की शक्ति - अपीलीय न्यायालय के पास यह शक्ति होगी की वह कोई भी डिक्री पारित करने या कोई ऐसा आदेश करे जो पारित कि जानी चाहिए थी या किया जाना चाहिए था और ऐसा या अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करे जो मामले में अपेक्षित हो और उस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील केवल डिक्री के भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थीयों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थीयों या पक्षकारों ने कोई अपील या आक्षेप फाइल न किया हो होगी और जहां, प्रतिपवादों में डिक्रियां हुई हो या जहां एक वाद में दो या अधिक डिक्रियां पारित की गई हो, वहाँ यह शक्ति सभी डिक्रियों या उनमें से किसी एक के बारे में प्रयोग की जा सकेगी यद्यपि ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील फाइल न की गई हो:

परंतु अपील न्यायालय धारा 35क के अधीन कोई भी आदेश किसी ऐसे आक्षेप के अनुसरण में नहीं करेगा जिस पर उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा आदेश नहीं किया है या ऐसा आदेश करने से इनकार किया है।

18. इस प्रावधान को *महंत धनगीर बनाम मदन मोहन* मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया था:

नियम 33 के तहत शक्ति का दायरा न केवल अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच, बल्कि प्रतिवादी और सह-प्रतिवादी के बीच भी किसी भी प्रश्न का निर्धारण करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। अपीलीय न्यायालय कोई भी डिक्री या आदेश पारित कर सकती है जो मामले की परिस्थितियों में पारित किया जाना चाहिए था। अपीलीय न्यायालय मामले की आवश्यकता के अनुसार ऐसी अन्य डिक्री या आदेश भी पारित कर सकती है। आदेश 41

> के नियम 33 में इस्तेमाल किए गए शब्द 'जैसा भी मामला हो' को व्यापक शब्दों में रखा गया है ताकि अपीलीय अदालत न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई भी आदेश या डिक्री पारित कर सके। तो फिर क्या बाधा होनी चाहिए? हमें बहुत से नहीं मिलती। हम कोई उदार व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यह नियम अपने आप में काफी उदार है। एकमात्र बाधा जो हम देख सकते हैं, वह ये हो सकती है: निचली अदालत के समक्ष पक्षकार अपीलीय अदालत के समक्ष मौजूद होने चाहिए। उठाया गया प्रश्न निचली अदालत के फैसले से उचित रूप से उठना चाहिए। यदि ये दो आवश्यकताएं हैं, तो अपीलीय अदालत निचली अदालत के फैसले या डिक्री के किसी भी हिस्से के खिलाफ किसी भी आपत्ति पर विचार कर सकती है। अपील में किसी भी पक्ष द्वारा इसका आग्रह किया जा सकता है। यह सच है कि नियम 33 के तहत अपीलीय अदालत की शक्ति विवेकाधीन है। लेकिन पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए पूछे गए सभी प्रश्नों का निर्धारण करना न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग है। अदालत को केवल तकनीकी बातों के आधार पर उस विवेक का प्रयोग करने से इनकार नहीं करना चाहिए।"

18. इसके अलावा, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पिछले वेतन के संबंध में अपनी कानूनी दलीलों के समर्थन में *दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय*[4] के फैसले पर सही भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

> "22. किसी कर्मचारी को उसी पद पर बहाल करने का विचार, जिस पर वह बर्खास्तगी, निष्कासन या सेवा समाप्ति से पहले था, का तात्पर्य यह है कि कर्मचारी को उसी स्थिति में रखा जाएगा जिसमें वह नियोक्ता द्वारा की गई अवैध कार्रवाई के बिना होता। किसी व्यक्ति की क्षति, जिसे पदच्युत कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या अन्यथा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो, को आसानी से पैसे के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है। ऐसे आदेश के पारित होने से, जिसका प्रभाव नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को विच्छेद करने पर पड़ता है, नियोक्ता की आय का स्रोत समाप्त हो जाता है। न केवल संबंधित कर्मचारी, बल्कि उसके पूरे परिवार को गंभीर प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। वे जीविका के स्रोत से

वंचित हो जाते हैं। बच्चे पौष्टिक भोजन और शिक्षा तथा जीवन में उन्नति के सभी अवसरों से वंचित हो जाते हैं। कई बार भुखमरी से बचने के लिए परिवार को रिश्तेदारों और अन्य परिचितों से उधार लेना पड़ता है। ये कष्ट तब तक जारी रहते हैं जब तक सक्षम न्यायिक मंच नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की वैधता पर निर्णय नहीं ले लेता। ऐसे कर्मचारी की बहाली, जो सक्षम न्यायिक/अर्ध-न्यायिक निकाय या न्यायालय के इस निष्कर्ष से पहले होती है कि नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, कर्मचारी को पूर्ण बकाया वेतन का दावा करने का अधिकार देती है। यदि नियोक्ता कर्मचारी को पिछला वेतन देने से इनकार करना चाहता है या परिणामी लाभ प्राप्त करने के उसके अधिकार का विरोध करना चाहता है, तो यह उसका विशेष रूप से अनुरोध करने और साबित करने का काम है कि बीच की अवधि के दौरान कर्मचारी लाभप्रद रूप से नियोजित था और समान परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहा था। नियोक्ता के अवैध कृत्य के कारण पीड़ित कर्मचारी को पिछला वेतन देने से इनकार करना अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कर्मचारी को दंडित करने और नियोक्ता को परिलब्धियों सहित बकाया वेतन का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करके पुरस्कृत करने के समान होगा।"

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

19. उन्होंने आगे *भुवनेश कुमार द्विवेदी बनाम हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड*[5] के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा था:

"अपीलकर्ता के पक्ष में दिए जाने वाले बकाया वेतन के मुद्दे पर, *शिव नंदन महतो बनाम बिहार राज्य* मामले में इस न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि यदि किसी कर्मचारी को उस प्रतिष्ठान/कंपनी की भूल या गलती के कारण सेवा से बाहर रखा जाता है जिसमें वह काम कर रहा था, तो कर्मचारी उस अवधि के लिए पूर्ण बकाया वेतन पाने का हकदार है, जब उसे अवैध रूप से सेवा से बाहर रखा गया था। फैसले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

8. ... वास्तव में, डिवीजन बेंच द्वारा पारित उपरोक्त संक्षिप्त आदेश का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से भी

परिचित नहीं था कि अपीलकर्ता को एक गलती के कारण सेवा से बाहर रखा गया था। निलंबन के कारण उन्हें सेवा से बाहर नहीं रखा गया, जैसा कि उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया है। इसलिए, निष्कर्ष स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को इस आधार पर पिछले वेतन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था कि उसने उस अवधि के लिए काम नहीं किया था जब उसे अवैध रूप से सेवा से बाहर रखा गया था। हमारी राय में, अपीलकर्ता उस अवधि के लिए पूरा वेतन पाने का हकदार था, जब उसे सेवा से बाहर रखा गया था।"

37. इसके अलावा, *हरियाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह* में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या अवैध छंटनी के प्रत्येक मामले में कर्मचारी को पिछला वेतन दिया जाना चाहिए। प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

"8. ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि हर मामले में जहां औद्योगिक न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष देता है कि सेवा की समाप्ति अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन है, पूरा पिछला वेतन दिया जाना चाहिए। चयन और नियुक्ति के तरीके और पद्धति जैसे कई कारक, यानी रिक्ति के उचित विज्ञापन के बाद या रोजगार कार्यालय से आवेदन आमंत्रित करने के बाद, नियुक्ति की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ, अल्पावधि, दैनिक वेतन, अस्थायी या स्थायी चरित्र, नौकरी के लिए आवश्यक कोई विशेष योग्यता और आदि को बकाया वेतन देने के संबंध में निर्णय लेते समय तौला और संतुलित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कारकों में से एक, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह सेवा की अवधि है, जो कर्मचारी ने नियोक्ता के साथ प्रदान की थी। यदि कर्मचारी ने काफी लंबी सेवा अवधि पूरी कर ली है और उसकी सेवाएं गलत तरीके से समाप्त कर दी गई हैं, तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसे पूरा या आंशिक बकाया वेतन दिया जा सकता है कि उसकी उम्र और उसके पास मौजूद योग्यता के आधार पर वह दूसरा रोजगार पाने की स्थिति में नहीं हो सकता है। हालाँकि, जहां किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की कुल लंबाई बहुत कम है, पूरी अवधि के लिए बकाया वेतन का पुरस्कार, यानी समाप्ति की तारीख से लेकर पुरस्कार की तारीख तक, जो कि हमारे अनुभव से पता चलता है,

अक्सर काफी बड़ा होता है, पूरी तरह से अनुचित होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है रोजगार की प्रकृति। स्थायी चरित्र की नियमित सेवा की तुलना अल्पकालिक या रुक-रुक कर होने वाले दैनिक वेतन वाले रोज़गार से नहीं की जा सकती, भले ही यह एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के लिए हो।"

20. इस प्रकार, उपरोक्त मामलों को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक न्यायाधिकरण की ओर से प्रतिवादी को पिछला वेतन देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं था, भले ही यह पाया गया हो कि कि अधिनियम की धारा 6-एन के तहत अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण समाप्ति का आदेश कानून में शुरू से ही शून्य है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समाप्ति की अवधि वर्ष 1975 में थी और नियोक्ता द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में 40 वर्षों से अधिक समय तक इस मामले को अनावश्यक रूप से चुनौती दी गई है, और आगे भी औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा बहाली का पुरस्कार/आदेश पारित करने के बाद भी, जिसमें नियोक्ता को उसे ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर पद देने का निर्देश दिया गया था, उसे उक्त पद की पेशकश करके उसे देने से इनकार कर दिया गया है जो ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद के बराबर नहीं है और इस प्रकार, उसे दिए गए पद पर रिपोर्ट न करने के लिए प्रतिवादी पर दोष मढ़ना, जो एक बार फिर नियोक्ता की ओर से अनुचित है।

21. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा मामलों की श्रृंखला में अवलोकित सिद्धांत "काम नहीं तो वेतन नहीं" का वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिति में कोई महत्व नहीं है क्योंकि ट्यूब-वेल ऑपरेटर के पद से कामगार की सेवाओं की समाप्ति जैसा कि ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने माना है, प्रथमतः कानून की दृष्टि से गलत है।

22. प्रतिवादी और उसके परिवार के सदस्य चार दशकों से अधिक समय से पीड़ित हैं क्योंकि उनकी आजीविका के स्रोत को अपीलकर्ता ने मनमाने ढंग से वंचित कर दिया है। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता और आजीविका के अधिकार को अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को वंचित कर दिया गया है जैसा कि *ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम और अन्य*[6] के मामले में हुआ था, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार व्यवस्था दी है:

“32. जैसा कि हमने याचिकाकर्ताओं के मामले को सारांशित करते समय कहा है, उनके तर्क का मुख्य मुद्दा यह है कि अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है और चूंकि, यदि उन्हें उनकी झुग्गी-झोपड़ी और फुटपाथ आवासों से बेदखल कर दिया गया तो वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे, इसलिए उनका निष्कासन उनके जीवन से वंचित होने के समान है और इसलिए असंवैधानिक है। तर्क के प्रयोजनों के लिए, हम इस आधार की तथ्यात्मक सत्यता मान लेंगे कि यदि याचिकाकर्ताओं को उनके आवास से बेदखल कर दिया गया, तो वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे। उस धारणा पर, हमें जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है कि क्या जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। हम उस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देखते हैं, वह यह कि ऐसा होता है। <u>अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार का दायरा व्यापक और दूरगामी है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, उदाहरण के लिए, मौत की सजा देकर और निष्पादित करके। यह जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उस अधिकार का एक समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीवन यापन के साधन यानी आजीविका के साधनों के बिना नहीं रह सकता है। यदि आजीविका के अधिकार को जीवन के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने का सबसे आसान तरीका उसे उसकी आजीविका के साधनों से हनन की हद तक वंचित करना होगा।</u> इस तरह का अभाव न केवल जीवन को उसकी प्रभावी सामग्री और सार्थकता से वंचित कर देगा, बल्कि जीवन को जीना असंभव बना देगा। और फिर भी, यदि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो इस तरह का अभाव कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं होगा। <u>वह, जो अकेले जीना संभव बनाता है, उस चीज़ को छोड़ दें जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उसे जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका के अधिकार से वंचित करें और आप उसे उसके जीवन से वंचित कर देंगे।</u> दरअसल, यह ग्रामीण आबादी के बड़े शहरों की ओर बड़े

पैमाने पर प्रवास की व्याख्या करता है। वे पलायन इसलिए करते हैं क्योंकि गांवों में उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। गांव में अपने चूल्हों और घरों को छोड़ने के लिए प्रेरित करने वाली प्रेरक शक्ति अस्तित्व के लिए संघर्ष, यानी जीवन के लिए संघर्ष है। जीवन और आजीविका के साधनों के बीच संबंध का प्रमाण इतना बेदाग है। उन्हें जीने के लिए खाना पड़ता है: केवल मुट्ठी भर लोग ही खाने के लिए जीने की विलासिता को वहन कर सकते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं, अर्थात् खा सकते हैं, केवल तभी जब उनके पास आजीविका का साधन हो। यही वह संदर्भ है जिसमें डगलस, जे. ने *बेकसी* में कहा था कि काम करने का अधिकार मनुष्य के पास सबसे मूल्यवान स्वतंत्रता है। यह सबसे कीमती स्वतंत्रता है क्योंकि, यह मनुष्य को जीवित रहने में सक्षम बनाती है और जीवन का अधिकार एक अनमोल स्वतंत्रता है। "जीवन", जैसा कि मुन्न बनाम इलिनोइस में फील्ड, जे. द्वारा देखा गया, का अर्थ केवल पशु अस्तित्व से कहीं अधिक है और जीवन के अभाव के खिलाफ निषेध उन सभी सीमाओं और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है। इस टिप्पणी को *खड़क सिंह बनाम यूपी राज्य* मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।"

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

23. इसलिए, इस न्यायालय के पूर्वोक्त न्यायिक निर्णयों के संबंध में, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता समाप्ति आदेश दिनांक 22.08.1975 से औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार की तिथि, यानी 24.02.1997 तक प्रतिवादी के पक्ष में 50% बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

24. जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले और दिनांक 18.07.2006 के आदेश में 24.02.1997 से 31.01.2005 की अवधि के लिए प्रतिवादी को पूर्ण बकाया वेतन देने का सवाल है, हम इसे बरकरार रखते हैं। अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान के आधार पर गणना करने के बाद प्रतिवादी को पूर्ण वेतन का भुगतान करने और उसे अन्य सभी मौद्रिक लाभ भी देने का निर्देश दिया गया है। अपीलकर्ता को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर उपरोक्त निर्देश का अनुपालन करना होगा।

25. तदनुसार, पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित पिछले वेतन के संबंध में संशोधन के साथ अपील खारिज की जाती है। स्थगन देने का दिनांक 11.12.2006 का आदेश निरस्त हो जाएगा। कोई लागत नहीं।

अपील निस्तारित की गई।

निधि जैन

---

1 (1995) पूरक(4) एससीसी 241

2 (1997) 6 एससीसी 723

3 (1999) 8 एससीसी 229

4 (2013) 10 एससीसी 324

5 (2014) 11 एससीसी 85

6 (1985) 3 एससीसी 545

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।